

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

डीबी केंद्रीय/उत्पाद शुल्क अपील संख्या 85/2018

आयुक्त, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर-। अब आयुक्त, केन्द्रीय
माल एवं सेवा कर, सूर्य नगर, अलवर।

----अपीलकर्ता

बनाम

डी केम प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, ई-527, रीको औद्योगिक क्षेत्र,
भिवाड़ी राज.

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री संदीप पाठक, एडवोकेट,
सुश्री वर्तिका मेहरा, एडवोकेट के
साथ।

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री एस. जयकुमार,
श्री कार्तिक जिंदल के साथ (वीसी
के माध्यम से)। श्री राज कुमार
शर्मा, एडवोकेट।

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमान. जस्टिस भुवन गोयल

आदेश

22/04/2024

अवनीश झिंगन (जे), मौखिक:

1. यह अपील केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35(जी) के अंतर्गत सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 20.09.2017 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।
2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रतिवादी फॉर्मल्डिहाइड और थिनर के निर्माण में लगा हुआ था। 24.09.2002 को प्रतिवादी के परिसर में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान एकत्र की गई जानकारी के आधार पर विभाग द्वारा स्थापित मामला यह था कि प्रतिवादी कच्चा माल प्राप्त किए बिना सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठा रहा था। अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी द्वारा लिया गया स्टैंड यह था कि भुगतान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया गया था। इयूटी का हिस्सा व्यक्तिगत लेजर खाते (पीएलए), ईआर -1 और आरटी -12 के माध्यम से संबंधित महीनों के

लिए भुगतान किया गया था, जो दर्शाता है कि पीएलए के माध्यम से भुगतान दायर किए गए थे। अंतिम उत्पाद के लिए बिक्री का विचार भी बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त हुआ था। मामला ट्रिब्यूनल में चला गया और 09.07.2007 के आदेश के तहत मामले को पुनर्विचार के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को वापस भेज दिया गया

"हम पाते हैं कि राजस्व का मामला यह है कि आवेदकों को इनपुट प्राप्त नहीं हुए थे और उन्हें केवल शुल्क भुगतान दस्तावेज प्राप्त हुए थे जिनके आधार पर उन्होंने क्रेडिट लिया। आवेदक का तर्क है कि इनपुट का उपयोग अंतिम उत्पाद के निर्माण में किया गया था जिस पर शुल्क का भुगतान किया गया था और वास्तव में प्राप्त क्रेडिट से अधिक शुल्क का भुगतान किया गया है। शुल्क का एक हिस्सा पीएलए के माध्यम से चुकाया गया है। आवेदक ने संबंधित महीनों के लिए ईआर.आई और आरई 12 रिटर्न दाखिल किए, जिसमें पीएलए के साथ-साथ क्रेडिट खाते के लिए शुल्क का भुगतान दिखाया गया। बैंक स्टेटमेंट की प्रतियां दर्शाती हैं कि भुगतान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से इनपुट के लिए किया गया था और अंतिम उत्पादों की बिक्री का भुगतान भी बैंकों के माध्यम से प्राप्त हुआ था। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस साक्ष्य पर विचार नहीं किया था। अपीलकर्ताओं ने अंतिम उत्पाद पर शुल्क का भुगतान किया, जो विवादित इनपुट से निर्मित है। इन परिस्थितियों में, हम पाते हैं कि यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पुनर्विचार के लिए एक उपयुक्त मामला है।

विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और शुल्क और जुर्माना की पूर्व जमा राशि को माफ करते हुए मामला न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को वापस भेज दिया जाता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी मामले का फैसला करेंगे। अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, अपीलकर्ताओं को 10 सितंबर 2007 को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। तत्पश्चात न्यायनिर्णायक प्राधिकारी सुनवाई की तिथि निर्धारित करेंगे और कानून के अनुसार मामले का निर्णय करेंगे।

3. रिमांड के अनुसरण में, दिनांक 12.02.2008 का आदेश पारित किया गया जिसमें पूर्व में की गई मांग को दोहराया गया। न्यायाधिकरण ने 20.09.2017 को अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। अतः वर्तमान अपील।

4. अपील है: वर्तमान में उठने वाला विधि का सारवान प्रश्न

(i) क्या न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 09.07.2007 के आदेश का प्रभाव सीमित रिमांड का था?

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि न्यायाधिकरण ने इस आधार पर अपील पर निर्णय लिया है कि आयुक्त को प्रतिप्रेषण इस निर्देश के साथ किया गया था कि कच्चे माल और अंतिम उत्पाद के भुगतान बैंकिंग माध्यमों से किए और प्राप्त किए जाने के साक्ष्य पर

विचार किया जाए। तर्क यह है कि मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया गया था और क्षेत्र को खुला छोड़ दिया गया था।

6. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का बचाव किया और तर्क दिया कि अपील में शामिल मुद्दों पर गुण-दोष के आधार पर भी निर्णय लिया जा चुका है। अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया, न कि केवल इस आधार पर कि रिमांड सीमित उद्देश्यों के लिए था।

7. उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा दलीलों का अवलोकन किया गया।

8. न्यायाधिकरण के दिनांक 09.07.2007 के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मामला पुनर्विचार हेतु आयुक्त को वापस भेज दिया गया है। रिमांड में कोई शर्त नहीं थी।

9. यह तर्क कि न्यायाधिकरण ने मुद्दों का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया, प्रतिवादी के मामले को पुष्ट नहीं करता। न्यायाधिकरण ने मुद्दों का निर्णय इस आधार पर किया कि रिमांड की शर्तों का पालन नहीं किया गया था और इससे प्राप्त निष्कर्षों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था।

10. विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और मामले को न्यायाधिकरण को वापस भेजा जाता है ताकि कानून के अनुसार अपील पर निर्णय लिया जा सके।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि अपील पर निर्णय करते समय न्यायाधिकरण विवादित आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगा तथा अपील पर नए सिरे से कार्यवाही करेगा।

12. यह देखते हुए कि निरीक्षण वर्ष 2002 में किया गया था, यह सराहनीय होगा यदि न्यायाधिकरण पक्षकारों के सहयोग से मामले के तथ्यों के आधार पर अपील का निर्णय यथाशीघ्र करने का प्रयास करे।

13. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

(भुवन गोयल), जे

(अवनीश झिंगन), जे

सुदीपक/एचएस/20रिपोर्ट योग्य:- हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी